



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रारिधकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 1977/वैशाख 10, 1899

No. 141]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1977/VAISAKHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1977

G S R. 205(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, Basappa Danappa Jatti, Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Madhya Pradesh cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution"),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State,

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State,

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198, clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, articles 208 to 211 (both inclusive); the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State,

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved,

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively.

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Madhya Pradesh General Clauses Act, 1957 (Madhya Pradesh Act 3 of 1958) as in force in the State of Madhya Pradesh and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State.

New Delhi,

B D JATTI,

The 30th April, 1977

Vice-President acting as President.

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi,

T C A. SRINIVASAVARADAN, Secy

The 30th April, 1977

ORDER

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 206(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Madhya Pradesh and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

New Delhi;

B D JATTI,

The 30th April, 1977

Vice-President acting as President

[No V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi.

T C. A. SRINIVASAVARADAN, Secy.

The 30th April, 1977

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 205 (अ) — राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है :

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति, बसप्पा बानप्पा जत्ती का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश राज्य का शासन भारत के संविधान (जिसे इस में इस के पश्चात "संविधान" कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार नहीं बताया जा सकता है ;

अतः अब मैं संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करने हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता हूँ कि मैं —

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी कृत्य और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने हाथ में लेता हूँ ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधान मंडल की शक्तियाँ समद के प्राधिकार द्वारा या अधीन प्रयोक्तव्य होंगी, और

(ग) निम्नलिखित अनुपगिक और पारिणामिक उपबन्ध करता हूँ जो इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये मुझे आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं; अर्थात् —

(i) इस उद्घोषणा के उपर्युक्त खंड (क) के आधार पर अपने हाथ में लिये गये कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक मैं ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा ;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबन्धों के प्रवर्तन को एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, अर्थात् :—

अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंडल को निदेश करने से है ;

अनुच्छेद 151 के खंड (2) उतना का भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

अनुच्छेद 163 और 164 ;

अनुच्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य सरकार के कार्यों का मंत्रियों के बीच आवंटन से है ; अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबंध राज्य की विधान सभा द्वारा सकल्प के पारित किये जाने से है ;

अनुच्छेद 174 का खंड (1) और खंड (2) का उपखंड (क) ; अनुच्छेद 175 में 178 तक (जिसमें में दोनों सम्मिलित हैं) ; अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उस अनुच्छेद का प्रथम परन्तुक और अनुच्छेद 180 और 181 ;

अनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सबलमों और भक्तों से है, अनुच्छेद 188, 189 193, 194, 195 तथा 196, अनुच्छेद 198; अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4),

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सबलमों और भक्तों से है; अनुच्छेद 208 से 211 तक (जिसमें यह दोनों सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक और खंड (3) का परन्तुक; और अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से है ;

(iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विधित की जाती है ;

(iv) संविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निदेश का अर्थ उस राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के प्रति निदेश लगाया जायगा और उस में राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति किसी निदेश का, जहां तक उस का संबंध उस के कृत्यों और उस की शक्तियों से है, अर्थात् जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद के प्रति निदेश लगाया जायगा, और विशिष्टतया अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निदेश का अर्थ क्रमशः राष्ट्रपति और संसद या उस के सदनों के प्रति निदेश लगाया जायगा ;

परन्तु इसमें की कोई बात अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 से लेकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें मे दोनों भी सम्मिलित है) अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपबन्धों पर प्रभाव नहीं डालेंगे और न राष्ट्रपति को इस खण्ड के उपखण्ड (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह ठीक समझे, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी;

(V) संविधान में राज्य के विधान मण्डल के या एतद्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत इस उद्घोषणा के आधार पर संसद् द्वारा या राष्ट्रपति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश हैं, और मध्य प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1957 (मध्य प्रदेश 1958 का अधिनियम 3), जिस रूप में मध्य प्रदेश राज्य में लागू है और साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 के 10 वें) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा मानो यह उस राज्य के विधान मण्डल का अधिनियम हो।

बसप्पा दानप्पा जत्ती,

नई दिल्ली;

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति।

30 अप्रैल, 1977

[सं० V/11013/3/77-एस एंड पी(डी-V)]

नई दिल्ली,

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव।

30 अप्रैल, 1977

आदेश

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1977

सा० का० नि० 206 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्व-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मेरे द्वारा आज 1977 को अप्रैल के तीसवें दिन जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) का अनुसरण करते हुए मैं एतद्वारा निवेश

देता हूँ कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के सभी कृत्य और सविधान के अधीन या उस राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर अपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के अध्याधीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

बसप्पा दानप्पा जत्ती,

नई दिल्ली ;
30 अप्रैल, 1977

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति।

[सं० V/11013/3/77-एस एंड पी (डी-V)]

नई दिल्ली ;
30 अप्रैल, 1977

टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

